

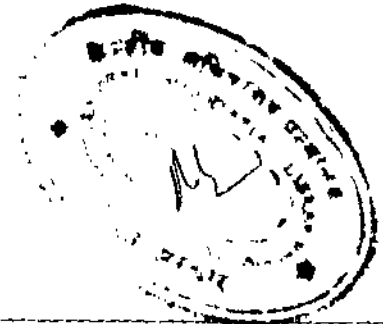


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 84]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 1995/फाल्गुन 11, 1916

No. 84] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 1995/PHALGUNA 11, 1916

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1995

सा० का० नि० 106(अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 (1993 का 65) की धारा 10 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (प्रतिकर का संदाय) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 (1993 का 65) अभिप्रेत है,

(ख) 'क्षेत्र' से अभिप्रेत है भूमि का वह क्षेत्र जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी तेल या प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोक्त या माप करने के लिए आशयित है,

(ग) 'निगम' से तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड अभिप्रेत है,

(घ) 'सक्षम प्राधिकारी' से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा कलक्टर के कृत्य करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कोई अधिकारी भी है,

(ङ) 'अधिभोगी' के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(i) कोई ऐसा व्यक्ति, जो उस भूमि का, जिसके अन्तर्गत भवन, यदि कोई है, भी है, जिसकी बाबत भाटक संवत् किया जाता है या संदेय है, भाटक या भाटक का कोई भाग स्वामी को तत्समय संदाय कर रहा है या संदाय करने के वायित्वाधीन है,

(ii) स्वामी, जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोगी है या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा है,

- (iii) किसी भूमि का जिसके अन्तर्गत भवन, यदि कोई है, भी है, भाटकमुक्ता अधिधारी,
- (iv) अनुज्ञापिधारी, जो किसी भूमि का, जिसके अन्तर्गत भवन, यदि कोई है, भी है, अधिधारी है, और
- (v) कोई ऐसा व्यक्ति, जो स्वामी को किसी भूमि के, जिसके अन्तर्गत उस पर निर्मित भवन भी है, उपयोग और अधिभोग के लिए नुकसान का संदाय करने के बाधित्व-धीन है,

(च) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. प्रतिकर के लिए दावों का फाइन किया जाना—

भूमि का कोई ऐसा अधिभोगी, जिसे निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसी क्षेत्र की माप या पूर्व-क्षण करने के दौरान भूमि को हानि या नुकसान हुआ है, मक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिकर का दावा,—

- (क) निगम के कर्मचारी द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के परिणाम-स्वरूप भूमि को की गई हानि या नुकसान के लिए, ऐसी हानि या नुकसान करने की तारीख से साठ दिन के भीतर,

फाइन कर सकेगा :

परन्तु मक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन के भीतर ऐसा दावा ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त हेतुक था।

- (ख) प्रतिकर के दावे के लिए आवेदन मक्षम प्राधिकारी को, लिखित रूप में, भूमि में या उस पर के उसके अधिकार, हक या हित और उन नुकसानियों के बारे में, जिनके बारे में यह अभिकथित है कि भूमि को की गई है, विनिर्दिष्ट और ऐसी अन्य विनिर्दिष्ट तथा/या ऐसे दस्तावेज, जिन्हें वह देना सुपंगन समझे, विनिर्दिष्ट करने हुए किया जाएगा।

- (ग) मक्षम प्राधिकारी, प्रतिकर का आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे और सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् प्रतिकर नियत करेगा तथा उसके पश्चात् इस प्रकार नियत प्रतिकर की रकम के बारे में पक्षकारों को सूचित करेगा।

4. प्रतिकर का जमा किया जाना :—निगम, नियम 3 के अधीन संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, प्रतिकर की रकम को ऐसे खजाने में और ऐसे लेखाशीर्ष के अधीन, जो उस निगम उनमें विनिर्दिष्ट किया जाए, जमा कर सकेगा।

5. दावेदारों को सूचना :—(1) जहां कई व्यक्ति धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन जमा की गई प्रतिकर की रकम में हितबद्ध होने का दावा करते हैं और मक्षम प्राधिकारी ने उस धारा की उपधारा (4) के अधीन ऐसे व्यक्तियों को, जो उसकी राय में, प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार हैं और उनमें से प्रत्येक को संदत्त की जाने वाली रकम को अवधारित किया है, वहां वह ऐसे सभी व्यक्तियों को, जिन्होंने प्रतिकर के दावे किए हैं, उसकी संसूचना भेजेगा।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई मक्षम प्राधिकारी का विनिर्दिष्ट स्वीकार नहीं करता है, तो वह, ऐसी संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन के अवधि के भीतर, मक्षम प्राधिकारी को उस आशय की लिखित रूप में सूचना देगा।

6. सूचना की तामील का ढंग, आदि—(1) इन नियमों के अधीन जारी की गई किसी सूचना या पत्र या पत्रित किसी आदेश को तामील, यथास्थिति, ऐसी सूचना पत्र या आदेश की प्रति उस व्यक्ति को, जिसके लिए वह आशयित है या उसके कुटुम्ब के किसी व्यक्ति सदस्य को परिदत्त करके या देकर या उस व्यक्ति के निवास या कारोबार के प्रायिक या अनिमित्त ज्ञात स्थान के पते पर रसीदी-रजिस्ट्री डाक द्वारा उसे भेजकर की जा सकेगी।

(2) जहां तामील करने वाला अधिकारी उपनियम (1) के अधीन सूचना, पत्र या आदेश की प्रति परिदत्त करता है या देता है, वहां वह उस व्यक्ति से, जिसको प्रति इस प्रकार परिदत्त की गई है या दी गई है, मूल पर पुष्टांकित तामील की अभिलेखिकृति के लिए हस्ताक्षर की अपेक्षा करेगा।

(3) जहां वह व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब का व्यक्ति सदस्य अभिलेखिकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है या जहां तामील करने वाला अधिकारी, सभी सम्पत्ति और व्यक्तिगत तत्परता का उपयोग करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति का पता नहीं चला सकता है और ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब का कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है, वहां तामील करने वाला अधिकारी सूचना, पत्र या आदेश की प्रति को वाह्य द्वार या सामान्य निवास के किसी अन्य सहजदृश्य भाग या ऐसे व्यक्ति के कारोबार के प्रायिक स्थान पर चिपका देगा और तब मूल को यह कथित करने हुए कि उसने एक प्रति इस प्रकार चिपका दी है, उन परिस्थितियों के बारे में, जिनके अधीन उसने ऐसा किया और उस व्यक्ति का, यदि कोई है, नाम और पता, जिसके द्वारा, यथास्थिति, निवास या कारोबार के प्रायिक या अनिमित्त ज्ञात स्थान को पहचाना गया था और जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपकाई गई थी, उस पर पुष्टांकित या उसमें उपाबद्ध एक रिपोर्ट सहित लोटा देगा।

(4) जहाँ वह व्यक्ति जिसे सूचना, पत्र या आदेश की तामील की जाती है, अव्यक्त या विकृतचित्त का व्यक्ति है, वहाँ सूचना, पत्र या आदेश की तामील, पूर्वोक्त गति में, यथास्थिति, ऐसे अव्यक्त या विकृतचित्त व्यक्ति के संरक्षक को की जाएगी।

7. केन्द्रीय सरकार को शर्त—(1) प्रतिकर की रकम के प्रद्वारण द्वारा व्यक्ति कोई पक्षकार, केन्द्रीय सरकार को शर्त, सक्षम प्राधिकारी से नियम 3 के अधीन संसूचना की प्राप्ति के नव्वे दिन के अग्रवान्, कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार को की जाने वाली प्रत्येक शर्त शर्तों द्वारा हस्ताक्षरित जापन के रूप में होगी और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव को सम्बोधित होगी तथा उस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उप शर्तों को जापनी या उसे समीचीन रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जाएगी। जापन के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति होगी जिसके बिना शर्तों की नहीं है।

(3) शर्तों के जापन में उप शर्तों के, जिसके विरुद्ध की गई है, आदेश के आदेश, सचिव रूप में और सुनिश्चित शर्तों में, किसी तर्क या वृत्तों के बिना उपस्थित की जाएगी और ऐसे आदेशों को रूप में संव्यवस्था किया जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन अनुज्ञापन समय के भीतर फाइल न की गई शर्तों का केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजूर कर दिया जाएगा, किन्तु यदि शर्तों में त्रुटिपूर्ण है, तो केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों को नामजूर करने से पूर्व, संबंध पक्षकार से किसी निश्चित समय के भीतर त्रुटियों को हटाने के लिए शर्तों करेगी और यदि वह ऐसा करता है, तो शर्तों को ग्रहण कर लिया जाएगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, उस तरीके में, जिससे शर्तों प्रत्यक्ष की गई है, एक सौ सप्ताह के भीतर यथासाध्य प्रक्रिया में शर्तों का विलिप्य का प्रयास करेगी।

[फाइल संख्या ओ-11021/2/93-गोपनीय/डी०३]

नजीब जंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 1995

G.S.R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 10 of the Oil and Natural Gas Commission (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 1993 (65 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Oil and Natural Gas Corporation Limited (Payment of Compensation) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Oil and Natural Gas Commission (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 1993 (65 of 1993);

(b) "area" means the area of land which is intended to prospect or measure for ascertaining the availability of any oil or natural gas under the provisions of the Act;

(c) "Corporation" means the Oil and Natural Gas Corporation Limited;

(d) "competent authority" means the Collector of a District and also includes any officer specially appointed by the State Government/Central Government to perform the functions of a Collector;

(e) "occupier" includes—

(i) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner the rent or any portion of the rent of the land including building, if any, in respect of which such rent is paid or is payable;

(ii) an owner in occupation of, or otherwise using his land or building;

(iii) a rent-free tenant of any land including building, if any;

(iv) a licensee in occupation of any land including building, if any; and

(v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any land including building constructed thereon;

(f) "section" means a section of the Act.

3. Filing of claims for compensation.—Any occupier of the land who has suffered loss or damage to the land while measuring or prospecting any area by any officer or employee of the Corporation, may file before the competent authority a claim for compensation,—

(a) for loss or damage caused to land by Corporation's employee as a result of exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 9, within sixty days from the date of causing of such loss or damage;

Provided that the competent authority may entertain such claim within thirty days after the expiry of the specified period, if he is satisfied that the applicant had sufficient cause for not making the application within such specified period.

(b) The application for the claim for compensation shall be made in writing to the competent authority specifying the particulars regarding his right, title or interest in or over the land and the damages alleged to have been caused to land and such other particulars and/or documents as he may deem relevant to be furnished.

(c) The competent authority shall, on receipt of the application for compensation, make such enquiry as he may deem fit and fix the compensation after hearing the parties concerned and thereafter inform the parties the amount of compensation, so fixed.

4. Deposit of compensation.—The Corporation, may within thirty days of the receipt of intimation under rule 3 deposit the compensation amount in such treasury and under such head of account as may be specified therein in that behalf.

5. Notice to claimants.—(1) Where several persons claim to be interested in the amount of compensation deposited under sub-section (3) of Section 9 and the competent authority has determined under sub-section (4) of that Section, the persons who in its opinion are entitled to receive the compensation and the amount to be paid to each of them it shall send intimation thereof to all the persons who have preferred claims for compensation.

(2) If any of the persons referred to in sub-rule (1) does not accept the decision of the competent authority he shall, within a period of thirty days of the receipt of such intimation the competent authority in writing to that effect.

6. Mode of service of notice, etc.—(1) Any notice or letter issued or any order passed under these rules may be served by delivering or tendering a copy of such notice, letter or order, as the case may be, to the person for whom it is intended or to any adult member of his family or by sending it by registered post with acknowledgement due addressed to that person at his usual or last known place of residence or business.

(2) Where the serving officer delivers or tenders the copy of the notice, letter or order under sub-rule (1), he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the original.

(3) Where the person or the adult member of the family of such person refuses to sign the acknowledgement, or where the serving officer, after using all due reasonable diligence, cannot find such person and there is no adult member of the family of such person, the serving officer shall affix a copy of the notice, letter or order on the outer door or some other conspicuous part of the ordinary residence or usual place of business of such person and then shall return the original with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he has so affixed a copy, the circumstances under which he did so and the name and address of the person, if any, by whom the usual or last known place of residence or business, as the case may be, was identified and in whose presence the copy was affixed.

(4) Where the person to be served with the notice, letter or order is a minor or a person of unsound mind, the notice, letter or order shall be served in the aforesaid manner, on the guardian of such minor or person of unsound mind, as the case may be.

7. Appeals to Central Government.—(1) Any party aggrieved by the determination of the amount of compensation may prefer an appeal to the Central Government, not later than ninety days of the receipt of the intimation from the competent authority under rule 3.

(2) Every appeal to the Central Government shall be in the form of the memorandum signed by the appellant, and shall be addressed to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and be presented to that officer personally or sent to him by registered post with acknowledgement due. The memorandum shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against.

(3) The memorandum of appeal shall set forth, concisely and under distinct head, the grounds of objection to the order appealed from without any argument or narrative; and such grounds shall be numbered consecutively.

(4) An appeal not filed within the time allowed under this rule shall be rejected by the Central Government, but if the appeal is defective in form, the Central Government, before rejecting such appeal, shall call upon the party concerned to remove the defects within a particular time, and if he does so the appeal shall be admitted.

(5) The Central Government shall endeavour to decide the appeal expeditiously, as far as practicable within one hundred and eighty days from the date on which the appeal is admitted.

[No. O-11021/2/93-ONG/D.III]

NAJEEB JUNG, Jt. Secy.